

**BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES
TRIBUNAL AT DEHRADUN**

Present: Hon'ble Mr. D.K. Kotia

----- Vice Chairman (A)

CLAIM PETITION NO. 21/SB/2015

Shrikant Gairola, S/o Late Sri Maheshwar Dutt Gairola, Presently posted as Section Officer, Anubhag-5, Law/Order, Police Headquarters, Uttarakhand, 11 Subhash Road, Dehradun.

.....Petitioner

VERSUS

1. State of Uttarakhand through Principal Secretary, Home, Civil Secretariat, Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand.
2. Superintendent of Police, Karmik, Uttarakhand Police Headquarters, 11, Subhash Road, Dehradun.
3. Additional Director General of Police (Administration), Uttarakhand, 11, Subhash Road, Dehradun.
4. Inspector General of Police, Uttarakhand Police Headquarters, 11, Subhash Road, Dehradun.

.....Respondents

Present: Sri Chandra Mohan, Counsel,
for the petitioner

Sri U.C.Dhaundiyal, A.P.O.
for the respondents

JUDGMENT

DATE: MAY 27, 2016

1. The petitioner has filed this petition for seeking the following relief:

“i) यह कि आवेदक के विरुद्ध निर्गत “अन्तिम आदेश” दिनांक 27.08.2013 जो आवेदक की चरित्र पंजिका में “उत्तराखण्ड (उ०प्र०) के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस

अधिकारियों / कर्मचारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 के अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 के नियम-14(2) के अन्तर्गत आपेक्षित परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश (अनुलग्नक-अ 1) प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा दिये गये हैं, को निरस्त करने के आदेश या निर्देश प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 को देने की कृपा करें:-

ii) यह कि आवेदक के अपीलिय प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.10.2013 को अस्वीकार करने के पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश पत्र संख्या:- डीजी-सात-6-2013(6) दिनांक 19.03.2014, को तथा आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2014 को अस्वीकार करने के अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश पत्र संख्या:- डीजी-सात-सात-2014(1) दिनांक 03.06.2014 को भी निरस्त करने के आदेश या निर्देश प्रत्यर्थी संख्या -1 को देने की कृपा करें।

iii) यह कि इस वाद का व्यय भी दिलाया जाये।

iv) यह कि अन्य जो भी प्रतिकर, माननीय अधिकरण उचित समझे, दिलाया जाये।”

2. The petitioner is working as Section Officer in Section -5 of the Law and Order Wing in the Police Headquarters, Dehradun. He was awarded minor punishment of ‘censure’ which has been challenged by the petitioner in this claim petition.

3. The facts in brief are that in an accident of jeep near Devprayag (district Tehri Garhwal) on 12.1.2013, out of 5 persons, four died. The Police with the help of local persons rescued the person who was alive. A Cabinet Minister of the State wrote to the Chief Minister of the State on 13.2.2013 to award 9 police personnel and 2 local persons for their good work in rescue operation.

4. While dealing with the matter of reward, there was a dispute as to which Section of the Police Headquarters would process it. Section -5 (Law and Order Wing) referred the matter to Section-7 (Karmik Wing) for further action but Section -7 was of the view that the matter pertained to Section-5. The correspondence regarding this also took place through

the senior officers--Superintendent of Police, Karmik and Deputy Inspector General of Police, Law and Order.

5. The Superintendent of Police, Karmik instituted a preliminary inquiry to determine as to which Section is responsible to deal with the matter and the Additional Superintendent of Police, Karmik was appointed to conduct the inquiry. It would be appropriate to reproduce below the letter of the Superintendent of Police, Karmik dated 13.3.2013 which was written to the Additional Superintendent of Police, Karmik:-

“अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक,
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 12-01-2013 को देवप्रयाग के पास देवप्रयाग सबधरखाल मोटरमार्ग पर एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें करीब 05 यात्री बैठे थे इस जीप के सड़क से नीचे लगभग 200 फीट नीचे खाई में गिर जाने पर 04 यात्रियों की मृत्यु हो जाने पर उनके शवों को एवं एक यात्री को बचाव दल के सदस्यों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए जीवित सुरक्षित निकाल लिये जाने के फलस्वरूप श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, संस्कृत, शिक्षा, पेयजल द्वारा बचाव दल के 09 पुलिस कर्मियों एवं जनता के 02 व्यक्तियों को साहसिक कार्य के लिए पुरुस्कृत किये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार को प्रकरण सन्दर्भित किया गया था। जिस पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड हेतु सन्दर्भित किया गया था।

उक्त सन्दर्भित पत्र को दिनांक 20-02-2013 को पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था को पृष्ठांकित किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था द्वारा पत्र को दिनांक 21-02-2013 को पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था को पृष्ठांकित कर भेजा गया था। जिसको पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था द्वारा दिनांक 21-02-2013 को ही अनुभाग-पॉच को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

इस पत्र को अनुभाग-पॉच द्वारा पत्रावली पर रखकर कोई कार्यवाही न करते हुए अनुभाग अधिकारी अनुभाग-पॉच द्वारा मात्र आधे कागज पर अपनी यह टिप्पणी अंकित करते हुए कि अनुभाग-पॉच में का0/व्य0 में अपराध पुरुस्कार (इनामी अपराधियों) सम्बन्धी पुरुस्कारों के परिपेक्ष्य में कार्य सम्पादित किया जाता है। प्राइवेट व्यक्तियों/महानुभावों द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने सम्बन्धी पुरुस्कारों का कार्य कार्मिक शाखा द्वारा सम्पादित किया जाता है, किसी अधिकारी को अग्रसारित नहीं

किया गया। उक्त पत्र दिनांक 22-02-2013 को पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था द्वारा पुलिस अधीक्षक, कार्मिक को पृष्ठांकित किया गया था जिसको दिनांक 22-02-2013 को ही अनुभाग-सात को मेरे द्वारा पृष्ठांकित करते हुए भेज दिया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुभाग-सात द्वारा यह अवगत कराते हुए कि कार्मिक शाखा द्वारा मात्र महानुभावों /जनता से नकद पुरस्कार सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं तथा सन्दर्भित पत्र में मा० मुख्यमंत्री अथवा मा० मंत्री जी द्वारा नकद धनराशि से पुरस्कृत न किये जाने के फलस्वरूप उक्त पत्र को मूल रूप में पत्र संख्या: विविध-ए०सी०-3/2013, दिनांक 07-03-2013 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था को इस आशय से भेजा गया कि मा० मुख्यमंत्री अथवा मा० मंत्री जी द्वारा नकद धनराशि से पुरस्कृत नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अनुभाग-पाँच कानून एवं व्यवस्था से किया जाना समीचीन होगा। इस पत्र को पुनः अनुभाग-पाँच से पत्र संख्या: डीजी-पाँच-10/2012, दिनांक 12-03-2013 के माध्यम से यह अंकित करते हुए कि यह प्रकरण किसी भी दृष्टिकोण से अपराधिक रिवाइड सम्बन्धी प्रकरण नहीं है, को कार्मिक शाखा से कार्यवाही कराने हेतु मुझे वापस भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी **GOOD WORK** के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर से रूपया 20 हजार तक, पुलिस महानिरीक्षक स्तर से रूपया 10 हजार तक, पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर से रूपया 5 हजार तक, एवं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक स्तर से रूपया 2,500/- तक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा रूपया 20 हजार से अधिक की पुरस्कार की धनराशि का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाता है।

उक्त से स्पष्ट है कि अनुभाग पाँच एवं सात से इस प्रकरण में कोई कार्यवाही न करते हुए प्रकरण को अनावश्यक रूप से इधर उधर घुमाया जा रहा है तथा उक्त सन्दर्भित पत्र पर उच्चाधिकारीगण द्वारा पारित किये गये आदेशों का उल्लंघन भी किया जा रहा है।

अतः इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पत्र संलग्न कर इस आशय से भेजे जा रहे हैं कि आप संलग्न पत्रों का गहनता पूर्वक परीशीलन करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कर दोषी का दोष निर्धारित कर अपनी जाँच आख्या 03 दिवस के अन्दर मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पत्र संख्या: सीए-एसपी(का०) -प्रा०जाँच/2013
दिनांक : मार्च 13, 2013

(मोहन सिंह बनग्याल)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून।”

6. The above letter gives a detailed account of various developments which took place between 12.1.2013 to 13.3.2013 in respect of processing the matter of reward. The inquiry officer was asked to conduct the preliminary inquiry on 13.3.2013 to find out who is at fault whether Section -5 or Section-7 and report was sought within 3 days.

7. It is pertinent to mention that on 13.3.2013 when the preliminary inquiry was ordered, the matter of reward was pending for further action in the Karmik Wing (Section-7) as is clear from the letter of the Deputy Inspector General of Police (Law and Order) dated 12.3.2013 written to the Superintendent of Police, Karmik. The same is reproduced below:

“पुलिस अधीक्षक,
कार्मिक पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कृपया अपने पत्र संख्या विविध-ए0सी- 3/2013 दिनांक 07/03/2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो दिनांक 12/01/2013 को देवप्रयाग-सबधरखाल मोटर मार्ग पर हुई जीप दुर्घटना के दौरान गहरी खाई से 04 यात्रियों के शवों को निकालने व 01 यात्री की जान बचाने वाले स्थानीय निवासियों व पुलिस कार्मिक को उनके द्वारा निभायी गयी प्रशंसनीय भूमिका के दृष्टिगत मा0 मंत्री, विधायी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा व पेयजल श्री मंत्री प्रसाद नैथानी के आग्रह पर स्थानीय निवासियों /पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- अवगत कराना है कि अनुभाग-5 का0/व्य0 में केवल आपराधिक रिवार्ड (Criminal Rewrd) सम्बन्धी कार्य अर्थात्, कुख्यात अपराधियों /गैंग इत्यादि को पुलिस कर्मियों /एस0टी0एफ0 /एस0ओ0जी0 कर्मियों द्वारा पकड़ने अथवा आपराधिक गैंग इत्यादि का पर्दाफाश किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित उच्चाधिकारियों /शासन द्वारा पूर्व में घोषित ईनामी राशि को प्रदत्त किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

3- सन्दर्भित प्रकरण से पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रकरण में मा0 मंत्री, श्री मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा गहरी खाई से शवों व 01 यात्री को निकालने के

फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के साथ –साथ स्थानीय निवासियों को भी पुरस्कृत किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से आपराधिक रिवार्ड (Criminal Rewrd) सम्बन्धी प्रकरण नहीं है, अतः उपरोक्त पत्र को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि सन्दर्भित प्रकरण में विभिन्न पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किये जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक शाखा से नियमानुसार यथोचित प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पत्रांक– डीजी–पॉच–10/2012
दिनांक:– मार्च 12, 2013

(पुष्कर सिंह सैलाल)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
अपराध/कानून व्यवस्था
उत्तराखण्ड।”

8. **As mentioned earlier, the inquiry officer (Additional Superintendent of Police, Karmik) was directed on 13.3.2013 to conduct the inquiry and report within 3 days. But the inquiry officer submitted his inquiry report on 21.5.2013 and found that the matter of reward should have been dealt with by Section-5 (Law and Order Wing) and the petitioner (who is Section Officer in Section-5) is guilty for not dealing with the matter and for the delay in the disposal of this matter.**

9. On the basis of the inquiry report, the Superintendent of Police, Karmik issued a show cause notice on 6.7.2013 to the petitioner as to why the censure entry be not given to him as a minor penalty under the “Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991” (applicable in the State of Uttarakhand).

10. The petitioner submitted the reply to the show cause notice on 10.7.2013 and denied the charge levelled against him.

11. The Superintendent of Police, Karmik considered the reply to show cause notice submitted by the petitioner and did not find the same satisfactory and found the petitioner guilty and awarded the following minor penalty of censure entry on 27.8.2013:-

“2013

वर्ष 2013 में पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-5 में निरीक्षक (एम)/ अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त रहते हुये दि० 12-01-2013 को देवप्रयाग के पास सबधरखाल मोटरमार्ग पर एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें करीब 05 यात्री बैठे थे इस जीप के सड़क से नीचे लगभग 200 फीट खाई में गिर जाने पर 04 यात्रीयों की मृत्यु हो जाने पर उनके शवों एवं एक यात्री को बचाव दल के सदस्यों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए जीवित सुरक्षित निकाल लिये जाने के फलस्वरूप श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, मा० मंत्री विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, पेयजल द्वारा बचाव दल के 09 पुलिस कर्मियों एवं जनता के 02 व्यक्तियों को साहसिक कार्य के लिए पुरुस्कृत किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को प्रकरण संदर्भित किया गया था । जिस पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड को बहादुरी के लिये सम्मान प्रदान किये जाने के संबंध में पृष्ठांकित किया गया था । संबंधित पत्र को पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था द्वारा दिनांक 21-5-2013 को अनुभाग-5 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने पर अनुभाग -5 द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए आपके द्वारा आधे अधूरी पर्चीनुमा कागज पर अपनी यह टिप्पणी अंकित करते हुये वापस कर दिया गया था कि “अनुभाग-5 में का०/व्य० में अपराध पुरुस्कार (इनामी अपराधियों) सम्बन्धी पुरुस्कारों के परिपेक्ष्य में कार्य सम्पादित किया जाता है, प्राइवेट व्यक्तियों/महानुभावों द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने सम्बन्धी पुरुस्कारों का कार्य कार्मिक शाखा द्वारा सम्पादित किया जाता है” । जो किसी अधिकारी को अग्रसारित नहीं किया गया था तथा उक्त पत्र दिनांक 22.2.2013 को पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था द्वारा पुलिस अधीक्षक, कार्मिक को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण में कार्यवाही विलम्ब से की गयी है, जिसके लिये अपने दायित्व के निर्वहन न करने तथा रिसीट के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब के लिये पूर्ण रूपेण दोषी है। आपका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति कार्य टालने की प्रवृत्ति कर्तव्यपालन में घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता का प्रतीक है। जिसकी घोर परिनिन्दा की जाती है।”

12. The petitioner filed an Appeal against the punishment order which was rejected on 19.3.2014. The Revision filed by the petitioner against the punishment order and appellate order was also rejected on 3.6.2014. Hence this petition.

13. The main ground on the basis of which the minor punishment of censure entry has been challenged by the petitioner is that it is not justified to punish him on the allegation of delay in disposing of the matter of reward as the matter remained pending in Karmik Wing from 12.3.2013 to 21.5.2013.

14. The claim petition has been opposed by respondents No. 1 to 4 denying the contentions of the petitioner and in their joint written statement, it has been stated that the inquiry against the petitioner has been conducted under Rule 14(2) of the Rules of 1991. The petitioner was given a show cause notice. The petitioner replied to the show cause notice and his reply was duly considered by the disciplinary authority. His reply/explanation was found unsatisfactory by the disciplinary authority. The disciplinary authority passed an order under Rule 14(2) of the said Rules and the petitioner was awarded minor penalty of 'censure'. The petitioner has been provided due opportunity to defend himself adhering to Rules and the principles of natural justice. The contention of the respondents is that the Rule 14(2) of the Rules of 1991 has been fully complied with. The appeal and revision of the petitioner against the order of the disciplinary and appellate authority were also duly considered and rejected as per Rules. The petition is, therefore, devoid of merit and liable to be dismissed.

15. The petitioner has also filed rejoinder affidavit and the same averments have been reiterated and elaborated which were stated in the claim petition.

16. I have heard both the parties and perused the record including the inquiry file carefully.

17. Learned counsel for the petitioner has argued that the petitioner cannot be held responsible for the delay in respect of disposal of the matter of reward. On 12.3.2013, Deputy Inspector General of Police, Law and Order had written to Superintendent of Police, Karmik mentioning that the matter was not related to Section-5 of the Law and

Order Wing and the same is to be dealt with by the Karmik Wing of the Police Headquarters.

18. Learned A.P.O. refuted the contention of the learned counsel for the petitioner and stated that the petitioner is responsible for the delay in disposing of the matter as the petitioner first dealt with the matter on 22.2.2013 and after that the matter was finally disposed of by him on 31.5.2013 and, therefore, he has been rightly held guilty for delay and the award of minor penalty of 'censure entry' is fully justified.

19. I have perused the punishment order of the Superintendent of Police, Karmik and the censure entry awarded to the petitioner (reproduced in paragraph 11 of this order). The 'censure entry' has been awarded to the petitioner for causing delay in disposal of the matter from 22.2.2013 onwards.

20. It is admitted that the petitioner initiated the action on the matter of reward on 22.2.2013 but as has been mentioned in the letter of Superintendent of Police, Karmik to the Additional Superintendent of Police, Karmik dated 13.3.2013 (reproduced in para 5 of this order) that on 12.3.2013, the matter was referred back by the Deputy Inspector General of Police, Law and Order to the Superintendent of Police, Karmik. This letter dated 12.3.2013 has been reproduced in para 7 of this order. In the said letter, the Deputy Inspector General of Police, Law and Order had written to the Superintendent of Police, Karmik that the matter is not related to the Section 5 of the Law and Order Wing and it is related to the Karmik Wing of the Police Headquarters and, therefore, necessary action is to be taken by the Karmik Wing. By perusing the record, it is also clear that from 13.3.2013 onwards, the matter remained pending with the Karmik Wing of the Police Headquarters. Thus, the matter was not pending with Section-5 of the Law and Order Wing from 13.3.2013 onwards.

21. Perusal of the record also reveals that there was dispute in the Police Headquarters as to who would process and dispose of the matter

of reward. There was lack of clarity between the Law and Order Wing and the Karmik Wing for disposing of the said matter as is clear from the correspondence which took place between the Superintendent of Police, Karmik and Deputy Inspector General of Police, Law and Order. Because of this reason, the Superintendent of Police, Karmik ordered an inquiry on 13.3.2013 to find out which Section is responsible to deal with the matter. The inquiry was conducted by the Additional Superintendent of Police, Karmik and in his inquiry report dated 21.5.2013, he found that the matter was related to the Section-5 of the Law and Order Wing. It is, therefore, clear that the Police Headquarters could decide the matter regarding Section which has to deal with the matter only on 21.5.2013.

22. It is very pertinent to mention here that the inquiry was ordered to be conducted on 13.3.2013 and the inquiry officer was directed to submit the inquiry report within 3 days. But there was inordinate delay in conducting the inquiry and the inquiry report was submitted on 21.5.2013 only.

23. In view of the above, it is clear that the matter was not pending with the petitioner from 13.3.2013 to 21.5.2013. The matter remained with the Karmik Wing of the Police Headquarters from 13.3.2013 onwards and the inquiry to decide as to which Section would deal with the matter was conducted from 13.3.2013 to 21.5.2013.

24. Thus, the punishment of 'censure entry' which has been awarded to the petitioner on the basis of the delay in disposal of the matter of reward from 22.3.2013 to 21.5.2013 is not based on the facts. The factual position as discussed above shows that the punishment order suffers from the patent error on the face of record. There is no evidence to show that the matter was pending with the petitioner from 22.2.2013 to 21.5.2013. On the contrary, the record clearly reveals that the matter during the said period was under inquiry and it was with the Karmik Wing of Police Headquarters. Under these circumstances, it would not be fair and just to hold the petitioner responsible for the delay for the

period 22.2.2013 to 21.5.2013. I am, therefore, of the opinion that the 'censure entry' awarded to the petitioner for causing delay from 22.2.2013 in disposing of the matter of reward is not based on any evidence and it cannot sustain in the eyes of law.

25. For the reasons stated above, the petition deserves to be allowed.

ORDER

The claim petition is hereby allowed. The impugned punishment order dated 27.08.2013, appellate order dated 19.03.2014 as well as revisional order dated 03.06.2014 are hereby set aside. The 'censure entry' entered in the character roll of the petitioner shall be expunged. No order as to costs.

D.K.KOTIA
VICE CHAIRMAN (A)

DATE: MAY 27, 2016
DEHRADUN

KNP